रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील -I) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, :
: सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :
: आंबावाडी, अहमदाबाद– 380015. :

क फाइल संख्या : File No : **V2(44)43 /Ahd-III/2015-16/Appeal-I** 7278 to 7282

ख अपील आदेश संख्या :Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-001-16-17**

दिनाँक Date : **25.04.2016** जारी करने की तारीख Date of Issue 4/5/16

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals-I)Ahmedabad

ग _____ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश सं _____ दिनाँक : _____ से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **575 to 579/REB/CEX/2015** Date: **12.05.2015**
Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Gandhinagar, A'bad-III.

ध अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. Sidwin Fabric Pvt. Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूवोक्त धारा को उप–धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

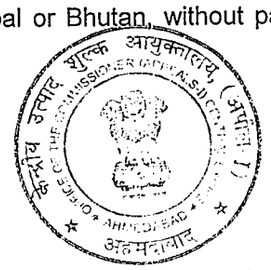

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए–8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल–आदेश एवं अपील आदेश की दो–दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35–इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर–6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/– फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/– की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:–
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35– ण्0बी/35–इ के अंतर्गत:–

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं

(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ–20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद–380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए–3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरूद्व अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/– फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/– फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/– फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any

nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि–1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall beer a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।
Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३५फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिनांक: ०६.०८.२०१४ जो की वित्तीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
(ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Sidwin Fabrics Pvt.Ltd.,Surevy No.898, At Dhundhar, Gambhol-Harsol Road, PO Gambhoi, NH-8, a. Himmatnagar(S.K.) 383001 (in short 'appellant') have filed an appeal against Order-in-Original No. 575 to 579/Reb/Cex/2015 dated 12.05.2015 (in short 'impugned order') passed by the Deputy Commissioner, Central Excise, Division Gandhinagar, Ahmedabad-III (in short 'adjudicating authority').

2. Briefly stated that the adjudicating authority rejected the rebate claims amounting to Rs.6,54679/- filed by the appellant under Rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 readwith Notifn. No.19/2004-CE(NT) dated 06.09.2004 on the ground that the appellant has failed to file Bill of Export as required under the conditions and procedure laid down in Circular No.29/2006-Customs dated 27.12.2006 vide impugned order.

3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant has filed the present appeal wherein they, interalia, have contested as under:

(a) the impugned order has been passed with utter disregard to the Circular No.29/2006-Cus. Dated 27.12.2006 which clarifies that Bill of Export needs to be filed only when the assessee calims export benefit. Rule 30 of the SEZ Rules provides that Bill of Export needs to be filed only in cases where export benefits are availed. As they have not claimed any export benefit such as drawback, advance licence, DEPB etc. and hence not filed Bill of Export.

(b) the GOI has held in its various orders that rebate claim cannot be denied only for non-submission of Bill of Export and rely upon case laws viz.

- Gujarat Organics Ltd-2014(314)ELT-981(GOI).
- Kei Industries Ltd-2014(313)ELT-895(GOI).
- Essel Propack Ltd.-2014(312)ELT-946(GOI).

(c) Impugned order may be set-aside and direct the authority concerned for sanction of rebate claim with applicable interest under Section 11BB of the Central Excise Act, 1944.

4. Personal hearing in the matter was held on 06.04.2016. Shri M.H. Raval, Consultant, appeared before me on behalf of the appellant and reiterated ground of appeal and pointed out Board's Circular No.29/2006-Cus. Dated 27.12.2006, Para 6 that shipping bill is not required. They also filed written submission dated 06.04.2014 wherein, interalia, submitted that rebate calim cannot be denied for procedural lapse when the duty paid nature of goods and supply the same to SEZ

is not under dispute and also rely upon case laws viz. P.K. Tunes & Fitings Pvt. Ltd.-2012(276)ELT-113(GOI); Naptune Power Plant Services Pvt. Ltd.-2015(321)ELT-160(GOI); that these decisions has been accepted by the deptt. and the issue has been settled that in case of export to SEZ when it is proved that the goods have been exported and the customs officers have signed on back of the ARE-1, the export made is not disputed and for procedural lapse the substantial benefit cannot be denied.

5. I have carefully gone through the appeal memorandum, submission made at the time of personal hearing and evidence available on records. The main issue to be decided is whether the filing of Bill of Export is mendatory or otherwise for claiming rebate for goods supplied to SEZ. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.

5.1 At the outset, I find that there is no dispute by the adjudicating authority for supply of the goods to the SEZ and its duty payment by the appellant. The rebate is claimed under Rule 18 of the Central Excise Rules, 2002 read with Notifn. No.19/2004-CE(NT) dated 06.09.2004. This notifn provides procedure for claiming rebate by the manufacturer/merchant exporter. So far as goods supplied to SEZ is concern, I find that the Board Has issued Circular No.29/2006-Cus. Dated 27.12.2006. The adjudicating authority has simply rejected the rebate claim on the ground that the appellant has not filed Bill of Export alongwith the rebate claim. In this regard, I find that the appellant has clearly stated in reply to the querry memo that they have not availed any export benefit like drawback etc. and hence no bill of export is filed. The Circular No.29/2006-Cus. Dated 27.12.2006 deals with *Implementation of Special Economic Zone Act, 2005 and Special Economic Zone Rules, 2006. Para 6 of this circular clearly provides that* the movement of goods from the place of manufacture to the SEZ shall be (i) on the basis of ARE-1 (in cases where export entitlements are not availed); (ii) on the basis of ARE-1 and Bill of Export (in cases where export entitlements are availed). Thus, it is crystal clear that only ARE-1 is sufficient where export entitlements are not availed. I find that the adjudicating authority has totally mis-construed the word 'export entitlement'. I find that 'export entitlement' means something extra benefit/incentive e.g. certain benefit under foreign trade scheme etc. As the goods supplied to SEZ is considered as 'deemed export' and there is no tax on export, excise duty paid on clearance of goods for export is given back in the form of 'rebate'. So, the rebate being legitimate right of the appellant under Rule 18ibid, it cannot be witheld simply by stating that rebate is export entitlement. I have also carefully gone through the case laws cited supra by the appellant. I find that facts of the case laws are similar to the present appeal and decision given by the GOI is applicable to the appellant ***mutatis-mutandis.***

5.2 As regards the claim of interest u/s 11BB of the Central Excise Act, 1944 by the appellant, I find that the appellant had filed 11 reabte claims on 15.09.2014 and 4 rebate claims on 13.01.2015 with the JAC whereas querry memos were issued on 10.02.2015 and 08.04.2015 respectively which were complied by the appellant on 14.03.2015 and 15.04.2015 (received by the JAC on 16.03.2015 and 17.04.2015) and the calims were rejected on 12.05.2015 vide impugned order. In this regard, I find that in terms of provisions contained in Section 11Bibid, the JAC has to decide it within a period of three months from the date of receipt of the application. I find that in both the case, the claims were decided by way of common rejection order(i.e impugned order) giving frivious reason discussed in Para 5.1 supra beyond time limit of three months stipulated in Section 11BBibid. Hence, I find that the appellant is entile for interest in terms of provisions of Section 11BBibid.

6. In view of the above discussion and findings, appeal filed by the appellant is allowed with consequential relief.

(UMA SHANKER)
COMMISSIONER (APPEALS-I)
CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.
Dt.25.04.2016

Attested

(B.A. Patel)
Superintendent (Appeals-I)
Central Excise,Ahmedabad.

BY SPEED POST/ R.P.A.D. TO:

M/s. Sidwin Fabrics Pvt.Ltd.,

Surevy No.898, At Dhundhar,

Gambhol-Harsol Road, PO Gambhoi, NH-8,

Ta. Himmatnagar(S.K.) 383001.

COPY TO:-

1. The Chief Commissioner of Central Excise, Ahmedabad.
2. The Commissioner of Central Excise, Ahmedabad-III.
3. The Dy. Commissioner, Cen. Excise. Division-Gandhinagar, Ahmedabad-III.
4. The Dy. Commissioner, Cen. Excise. (Systems), Ahmedabad-III. (for uploading the order on the website).
5. Guard file.
6. P. A. file